

Title: Need to provide funds for payment of wages to workers under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Balaghat and Seoni districts in Madhya Pradesh.

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है। जिसके अंतर्गत बालाघाट जिले एवं सिवनी जिले में विगत 4 माह से मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है। बालाघाट जिले एवं सिवनी जिले के सभी सरपंचों ने एम.आई.एस. पूर्ण कर के भेज दिया है। बालाघाट जिले, सिवनी जिले के सरपंच मजदूरों की मजदूरी के पेमेंट के लिए आन्दोलित हैं। जिसके कारण तीव्र आक्रोश व्याप्त है। बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित, अति पिछड़ा जिला है और उद्योगविहीन जिला है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलने के कारण मजदूर राज्य से बाहर पलायन कर रहे हैं। सुबह से शाम तक सरपंचों के घर बाहर चक्कर लगाते हैं। जिला पंचायत द्वारा मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद भोपाल से बालाघाट के लिए 85 करोड़ रुपये एवं जिला पंचायत सिवनी ने मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद भोपाल से सिवनी जिला के लिए 50 करोड़ रुपये की तत्काल माँग की है। परन्तु मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद द्वारा इन दोनों जिलों में राशि प्रदान नहीं की गई है। सितम्बर महीना त्योंहारों का महीना है। मनरेगा योजना के मजदूरों को समय पर पैसा नहीं मिलने से ग्राम पंचायत के सरपंचों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच लोग साहूकारों से ब्याज पर पैसे लेकर मजदूरों को भुगतान कर रहे हैं।

अतएव माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से माँग है कि केन्द्रीय टीम भेज कर इसकी जाँच की जाये। मजदूरों की मजदूरी में हुए विलंब में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए एवं बालाघाट, सिवनी जिला में मनरेगा की राशि तत्काल प्रदान की जाये।